

Title: Regarding delay in procurement of foodgrains by the Government.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान इलाका है। यहां के कृषि पर आधारित 80 प्रतिशत लोग निर्भर हैं, चाहे वे कृषक हों या मजदूर हों। प्रकृति के विरुद्ध जाकर किसानों ने परिश्रम से धान का उत्पादन किया है। 30 लाख टन बिक्री योग्य धान किसानों के खलिहानों में पड़ा हुआ है। दिसंबर माह बीतने जा रहा है जबकि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पंजाब और हरियाणा राज्यों में धान की खरीद समाप्त हो चुकी है और बिहार में एक छटांग भी धान की खरीद नहीं हुई। बिहार सरकार और भारत सरकार की उदासीनता है। भारत सरकार की गारंटी है कि किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते 1058 रुपये के बदले में 600-700 रुपये प्रति विंटल धान की बिक्री करनी पड़ रही है। यह लाभकारी मूल्य नहीं है, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अगर किसानों को 1058 रुपये मिलते तो शायद उसके हाथ में 50 या 100 रुपये बचत के रूप में आते। किसान 300-350 रुपये प्रति विंटल घाटा उठाकर बेच रहे हैं। यह लगातार सात वर्षों से हो रहा है। प्रति वर्ष किसानों की बिक्री योग्य अनाज पर 3000-4000 करोड़ रुपये की पूंजी समाप्त हो रही है। यह ठीक है कि देश के अन्य हिस्सों की तरह बिहार के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। यदि आत्महत्या करना ही उनके अधिकार की प्राप्ति का साधन है तो मैं समझता हूं कि यह सोच सही नहीं है। किसानों ने बड़े परिश्रम से उत्पादन किया है और उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं गारंटी दी गई है इसलिए एफसीआई एवं बिहार सरकार की संस्थाओं के माध्यम से अनाज की खरीद की जाए।